



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 975]
No. 975]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 27, 2003/कार्तिक 5, 1925
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2003/KARTIKA 5, 1925

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2003

का.आ. 1236(अ).—केन्द्रीय सरकार ने प्रस्तावित नए नगरों के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने तथा ऐसे मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए एक विशेषज्ञ दल गठित किया था जिसने अपनी रिपोर्ट 1989 में प्रस्तुत कर दी थी। सरकार ने उद्योग, घरेलू, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट आदि सहित विभिन्न स्रोतों के प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत गंगा कार्य योजना चरण-1 के अतिरिक्त 18 राज्यों में 31 नदियों के आसपास स्थित 157 शहरों में प्रदूषण निवारण कार्य भी शुरू किए हैं। इन प्रयासों के बावजूद गंगा कार्य योजना सहित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सीवरेंज और सीवेज शोधन क्षमता का संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा पर्याप्त रूप से अनुसंधान नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के उद्देश्यों को आंशिक रूप से पूरा किया जा रहा है।

परियोजनाओं से आर्द्रभूमि, झीलों, नदियों और तटीय जल सहित पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जो बच्चों सहित स्थानीय जनता के लिए गम्भीर स्वास्थ्य खतरा बन रहा है। पंचायत क्षेत्र में घरों के निर्माण की योजनाओं को केवल सैप्टिक टैंक की व्यवस्था के बाद ही अनुमोदित किया जाता है। किसी औद्योगिक परियोजना के लिए बहिस्त्राव शोधन संयंत्र आवश्यक है और औद्योगिक संपदा के लिए सामूहिक बहिस्त्राव शोधन संयंत्र आवश्यक है। दूसरी ओर, स्थानीय

निकाय/विकास प्राधिकरण पर्यावरण की ओर ध्यान दिए बिना विभिन्न श्रेणी और आकार की नई निर्माण परियोजना को अनुमोदित कर रहे हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सी) 1985 की सं० 4677 में 1994 की रिट याचिका संख्या 725 के साथ आई ए सं० 20,21, 1207, 1183, 1216 और 1251 में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में एक समाचार 'एंड क्वार्टर फ्लोज द मैली यमुना' बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और यमुना नदी के प्रदूषण से संबंधित अन्य मामले के संबंध में 4 दिसम्बर, 2001 को नीचे दिए अनुसार टिप्पणी की।

"विद्वान सलिसिटर जनरल ने कहा कि शहर आयोजना के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों को लागू किया जाएगा और शहर आयोजना के संबंध में जब कभी भी कोई निर्णय लिया तो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन को शामिल किया जाए, मंजूरी प्राप्त की जाए और तब निर्णय लिया जाए। दुर्भाग्यवश, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत नियमों में शहर आयोजना शामिल नहीं है। इस पहलू के संबंध में विद्वान सलिसिटर जनरल न्यायालय को तर्क एवं सुझाव देना चाहते हैं कि यमुना नदी को इतिहास बनने से रोका जाने के लिए क्या प्रभावी आदेश पारित किए जा सकते हैं। केन्द्रीय सरकार को विचार करना चाहिए और न्यायालय को सुनवाई की अगली तारीख पर सूचित करना चाहिए कि क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत नियमों को संशोधित नहीं किया जाना चाहिए ताकि शहरी आयोजना अधिनियम के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अपेक्षित हो।"

जबकि केन्द्रीय सरकार निरंतर प्रदूषित हो रही नदियों और अन्य जल निकायों को गम्भीरता से लिया है और इन जल निकायों में जल गुणता की और अधिक बिगड़ती स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि नए टाऊनशिप, औद्योगिक टाऊनशिप, आवासीय बस्तियों, वाणिज्यिक कॉम्प्लैक्स, होटल कॉम्प्लैक्स, अस्पताल, कार्यालय कॉम्प्लैक्स आदि के निर्माण से संबंधित नई परियोजनाओं जो 1000 अथवा इससे अधिक लोगों के लिए होंगी या जिनमें 50,000 लीटर प्रतिदिन या इससे अधिक मलजल का उत्सर्जन होगा या 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक का निवेश किया गया होगा और 50 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र वाली नए

औद्योगिक संपदाओं, चाहे उनका क्षेत्र कुछ भी क्यों न हो की यदि प्रदूषण क्षमता अत्यधिक है तो उन्हें पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अंतर्गत लाया जाना प्रस्तावित है।

और जबकि प्रस्ताव निम्निलिखित निबंधनों के अध्याधीन होगा, अर्थात्:

- (1) प्रस्तावित परियोजना को चरणबद्ध रूप में अथवा मापदण्डों में कार्यान्वित करने के प्रयोजन से परियोजना प्रस्तावक को संपूर्ण परियोजना, की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। सभी चरणों या मापदंडों को शामिल करते हुए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के अन्तर्गत समीक्षा के लिए प्रस्तुत करनी होगी।
- (2) प्रारूप अधिसूचना के लंबित होने के दौरान अत्यावश्यक प्रकार की परियोजनाओं को शुरू करने के प्रयोजन से परियोजना प्रस्तावक के लिए परियोजना से अधिक मात्रा में उत्पन्न मलजल के लिए वर्तमान मलजल शोधन संयंत्र में उपलब्ध मलजल शोधन क्षमता के संबंध में संबंधित स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। सरकार द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी के लिए ऐसी परियोजनाओं पर सभी दस्तावेजों की जांच की शर्त के साथ सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है।
- (3) नई निर्माण परियोजनाएं, जिनका निर्माण कार्य इस प्रारूप अधिसूचना के जारी होने की तारीख तक कुरसी स्तर तक नहीं पहुंचा है, को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अन्तर्गत स्वीकृति लेना अपेक्षित होगा।
- (4) नये औद्योगिक संपदाओं के मामले में, जहां निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है या इस प्रारूप अधिसूचना के जारी होने की तारीख से कुल स्वीकृत लागत की 25 प्रतिशत से अधिक राशि खर्च नहीं हुई है वहां प्रारूप प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अन्तर्गत मंजूरी लेनी अपेक्षित होगी।
- (5) उक्त खण्ड 3 और 4 के अन्तर्गत शामिल परियोजनाओं के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन इस प्रारूप अधिसूचना को अन्तिम रूप दिए जाने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

और जबकि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की संख्या का.आ. 60 (अ), दिनांक 27 जनवरी, 1994 की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार किसी गतिविधि या किसी परियोजना के उपक्रम के विस्तार या आधुनिकीकरण पर कतिपय प्रतिबंध और निषेध आरोपित किए

हैं जब तक कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दे देती ।

इसलिए अब उक्त अधिसूचना के निम्नलिखित प्रारूप संशोधन, जिसे केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा 2 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम 3 के खंड (घ) के साथ पठित उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित करती है और इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित करती है और एतद द्वारा ये नोटिस देती है कि उक्त प्रारूप संशोधन पर राजपत्र जिसमें उक्त मसौदा संशोधन उल्लिखित है उसकी प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से 60 दिन की अवधि के समाप्त होने के पश्चात विचार किया जाएगा ।

कोई व्यक्ति जिसे उक्त प्रारूप संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति हो अथवा उसका कोई सुझाव हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ लिखित रूप में एवं निर्धारित अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003. को भेज सकता है ।

प्रारूप संशोधन

उक्त अधिसूचना में

- (i) उप पैरा (च) के पश्चात पैरा 3 में निम्नलिखित उप पैरा जोड़े जाएंगे: नामतः :-
- (छ) 1000 व्यक्तियों अथवा इससे कम व्यक्तियों के लिए नए टाउनशिप्स, औद्योगिक टाउनशिप्स, रिहाइशी कालोनियों, व्यावसायिक परिसरों, होटल परिसरों, अस्पतालों, कार्यालय परिसरों सहित अनुसूची 1 की प्रविष्टि 31 के अन्तर्गत आने वाली अथवा प्रतिदिन 50,000 लीटर प्रतिदिन अथवा इससे कम मलजल निकासी करने वाली अथवा 50 करोड़ या इससे कम के परिवेश की कोई निर्माण परियोजना ।
- (ज) ऐसी औद्योगिक संपदाओं जिनका क्षेत्र कुछ भी हो लेकिन जिनमें प्रदूषण की संभाव्यता अधिक हो, को छोड़कर 50 हेक्टेयर अथवा इससे कम क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को स्थान देने वाली औद्योगिक संपदाओं सहित अनुसूची-1 की प्रविष्टि 32 के अन्तर्गत आने वाली कोई औद्योगिक संपदा ।

स्पष्टीकरण:- उप पैराओं (छ) और (ज) के अन्तर्गत चरणबद्ध ढंग से अथवा माड्यूलस आधार पर प्रस्तावित परियोजना को क्रियान्वित करने के इच्छुक किसी परियोजना प्रस्तावक

द्वारा समूची परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसमें पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अन्तर्गत मूल्यांकन हेतु सभी चरणों अथवा माड्यूलों को शामिल किया जाएगा, प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) मद सं० 30 के बाद अनुसूची -I में निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएंगी:-

31 नई निर्माण परियोजनाएं

32 नई औद्योगिक संपदाएं

(iii) अनुसूची II में पैरा 5 में उप-पैरा (च) के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"(च)(i) प्रस्तावित गतिविधियों के फलस्वरूप, प्राप्ति जल निकाय में छोड़े जाने वाले मौजूदा औद्योगिक बहिस्त्रावों और घरेलू मलजल व उसके वर्धित भार की मात्रा तथा उसके शोधन संबंधी विवरण।

(ii) नगर ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट, औद्योगिक बहिस्त्राव तथा घरेलू मल-जल सहित ठोस अपशिष्टों के निपटान से पूर्व व उसके बाद प्राप्ति निकाय में जल की मात्रा व गुणवत्ता;

(iii) भूमि पर छोड़े जानेवाले औद्योगिक बहिस्त्राव एवं घरेलू सीवेज की मात्रा और भूमि की किस्म।

(iv) पैरा 6 में, उप पैरा (क) के लिए निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"(क) नगर ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्टों सहित उत्सर्जित ठोस अपशिष्टों की किस्म व मात्रा।"

[सं. जेड-11011/1/2002-आई ए-1]

आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 27-1-1994 की सं. का.आ. 60(ई) के अन्तर्गत प्रकाशित की गई थी और तदुपरांत इसमें दिनांक 4 मई, 1994 की सं० का.आ. 356 (ई), दिनांक 10 अप्रैल, 1997 की सं० का.आ. 318 (ई), दिनांक 27 जनवरी, 2000 की सं० का.आ. 73 (ई), दिनांक 13 दिसम्बर, 2000 की सं० का.आ. 1119 (ई), दिनांक 1 अगस्त, 2001 की सं० का.आ. 737 (ई), दिनांक 21 नवम्बर, 2001 की सं०

का.आ.01148 (ई), दिनांक 13 जून, 2002 की सं० का.आ. 632 (ई), दिनांक 28 फरवरी, 2003 की सं० का.आ. 248 (ई), दिनांक 7 मई, 2003 की सं० का.आ. 506 (ई), दिनांक 4 अगस्त, 2003 की सं० का.आ. 891 (ई) तथा दिनांक 12 सितम्बर, 2003 की सं० का.आ. 1087 (ई) के अनुसार संशोधन किया गया ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2003

S.O. 1236(E).— Whereas, the Central Government recognising the need for evolving procedures for the environmental impact assessment of proposed new towns as also laying down broad guidelines for such assessment, constituted an Expert Group which submitted its report during 1989. The Government is implementing various measures for control of pollution from various sources including industrial, domestic, bio-medical wastes etc. Under the National River Conservation Plan (NRCP), the pollution abatement works in 157 towns along 31 rivers in 18 States have been undertaken in addition to Ganga Action Plan Phase-I. Despite these efforts, the sewerage system and sewage treatment capacity already provided under NRCP including the Ganga Action Plan are not adequately maintained by the respective local bodies, resulting in partial achievement of the objectives of NRCP;

And whereas, such projects have adverse impact on environment including wetlands, lakes, rivers and coastal waters posing serious health hazards to the local population including children. Even for construction of a house in a Panchayat area, plans are approved only after the provision of a septic tank. For an industrial project, an effluent treatment plant is necessary and for an industrial estate a common effluent treatment plant is necessary. On the other hand, local bodies/development authorities in towns have been approving new construction projects of various categories and sizes without any concern for the environment;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court in the Writ Petition (C) No. 725 of 1994 with I.A. No.20,21,1207,1183,1216 and 1251 in Writ Petition (C) No.4677

of 1985 in the matter of news item published in Hindustan Times titled "And Quiet Flows the Maily Yamuna" Vs. Central Pollution Control Board and Others, observed on 4th December, 2001, as under:

"The learned Solicitor General submits that in relation to town planning the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 would be applicable and whenever any decision is taken in regard to town planning, environment impact assessment must first be undertaken, clearance obtained and then the decision taken. Unfortunately, the Rules under Environment (Protection) Act as such do not cover town planning. In regard to this aspect, the learned Solicitor General wants to address arguments and give suggestions to the Court as to what effective orders can be passed with a view to prevent the river Yamuna from becoming history. The Central Government should also consider and inform the Court on the next date of hearing whether it should not amend the Rules under the Environment (Protection) Act so as to require the environment impact assessment for the purposes of the town planning Acts."

And whereas, the Central Government took a serious view of continuing pollution of rivers and other water bodies and in order to control further deterioration of water quality in these water bodies, it is felt necessary that new projects relating to construction of new townships, industrial townships, settlement colonies, commercial complexes, hotel complexes, hospitals, office complexes for 1,000 persons and above or discharging sewage of 50,000 litres/day and above or with an investment of Rs. 50 crores and above and new industrial estates having an area of 50 hectares and above and the industrial estates irrespective of area if their pollution potential is high, are proposed to be brought under the purview of Environment Impact Assessment Notification;

And whereas, the proposal shall be subject to the following conditions, namely:-

- (1) Project proponent intending to implement the proposed project in a phased manner or in modules, shall be required to submit the detailed project report of the entire project covering all phases or modules for appraisal under Environment Impact Assessment.

- (2) Project proponent intending to take up projects of very urgent nature during the pendency of the draft Notification shall be required to submit a certificate from the concerned local bodies/authorities with regard to the availability of sewage treatment capacity in their existing sewage treatment plant for incremental quantity to be generated by the project. Such projects can be considered by the Government for environmental clearance on a priority basis on the receipt of the complete proposal with all relevant documents subject to verification of such documents.
- (3) New construction projects where construction work has not come up to the plinth level on the date of issue of this draft Notification shall require clearance under the Environment Impact Assessment Notification.
- (4) In the case of new Industrial Estates, where the construction work has not commenced or the expenditure does not exceed 25% of the total sanctioned cost on the date of issue of this draft Notification shall require clearance under Environment Impact Assessment Notification.
- (5) In respect of projects covered under Clauses 3 and 4 above, application for environmental clearance shall be submitted by the project proponent within 30 days of finalization of this draft Notification.

And whereas, by Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No.S.O.60(E), dated the 27th January, 1994 the Central Government imposed certain restrictions and prohibitions on the expansion and modernisation of any activity or the undertaking of any project unless environmental clearance has been accorded by the Central Government or the State Government in accordance with the procedure specified therein;

Now, therefore, the following draft amendments to the said Notification, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft amendments shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days

from the date on which copies of the Gazette containing the said draft amendments are made available to the public;

Any person desirous of making any objection or suggestion in respect of the said draft amendments may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003.

DRAFT AMENDMENTS

In the said Notification, -

(i) in para 3, after sub-para (f), the following sub-paras shall be inserted, namely :-

“(g) any construction project falling under entry 31 of Schedule-I including new townships, industrial townships, settlement colonies, commercial complexes, hotel complexes, hospitals, office complexes for 1,000 (one thousand) persons or below or discharging sewage of 50,000 (fifty thousand) litres per day or below or with an investment of Rs.50,00,00,000 (Rupees fifty crores) or below;

(h) any industrial estate falling under entry 32 of Schedule-I including industrial estates accommodating industrial units in an area of fifty hectares or below but excluding the industrial estates irrespective of area if their pollution potential is high;

Explanation. - Any project proponent intending to implement the proposed project under sub-paras (g) and (h) in a phased manner or in modules, shall be required to submit the detailed project report of the entire project covering all phases or modules for appraisal under Environment Impact Assessment Notification”;

(ii) in Schedule-I, after item 30, the following items shall be added namely:-

“ 31. new construction projects

32. new industrial estates”;

(iii) in Schedule-II, in para 5, for sub-para (f), the following sub-para shall be substituted, namely:-

- “(f) (i) The quantum of existing industrial effluents and domestic sewage with incremental load to be released in the receiving water body due to the proposed activities along with treatment details;
- (ii) The quantum and quality of water in the receiving body before and after disposal of solid wastes including municipal solid wastes, biomedical wastes, hazardous wastes, industrial effluents and domestic sewage;
- (iii) The quantum of industrial effluents and domestic sewage to be released on land and type of land”;
- (iv) In para 6, for sub-para (a), the following sub-para shall be substituted, namely:-
- “(a) Nature and quantity of solid wastes generated including municipal solid wastes, biomedical wastes, hazardous wastes and industrial wastes.”

[No. Z-11011/1/2002-IA-I]

R. CHANDRA MOHAN, Jt. Secy.

Note: The principal Notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 60 (E) dated 27-1-1994 and subsequently amended vide S.O. 356(E) dated 4th May, 1994, S.O. 318 (E), dated 10th April, 1997, S.O. 73(E) dated 27th January, 2000, S.O. 1119 (E) dated the 13th December, 2000, S.O., 737(E) dated 1st August, 2001, S.O. 1148 (E) dated 21st November, 2001, S.O. 632 (E) dated the 13th June, 2002, S.O. 248 (E) dated the 28th February, 2003, S.O. 506(E) dated the 7th May, 2003, S.O. 891(E) dated the 4th August, 2003 and S.O. 1087(E) dated the 22nd September, 2003.